संख्या :20|35%09(150)2019/XXVII(1)/2024

प्रेषक.

दिलीप जावलकर, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

त.समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/ सचिव/ प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
त.समस्त विभागाध्यक्ष/वित्त नियन्त्रक,

उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक :22 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत

किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2024" के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में समस्त सुसंगत मदों में प्रावधानित धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही नहीं वरन समस्त प्रशासनिक विभागों का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जायेगा, जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग—01 के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय—समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाय। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण—वितरण अधिकारी को किया जायेगा।
- 3— समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा सर्वप्रथम आय—व्ययक में प्रावधानित धनराशि से राज्य आकिरमकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिपूर्ति ऑनलाइन माध्यम से उसी लेखाशीर्षक / मद से सुनिश्चित की जायेगी, जिससे राज्य आकिरमकता निधि से धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से पूर्व उस लेखाशीर्षक से अन्य कोई धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। राज्य आकिरमकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने